केंद्रीय बजट 2024-25: एक आकलन

आयुषी खंडेलवाल, हर्षिता यादव, आकाश राज, सक्षम सूद, इप्सिता पाढ़ी, बिचित्रानंद सेठ, अनूप के. सुरेश और समीर रंजन बेहरा द्वारा ^

केंद्रीय बजट 2024-25 का उद्देश्य राजकोषीय सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं को सरल बनाने का प्रस्ताव किया गया है और पूंजीगत व्यय बढ़ाने और सरकारी खर्च की गुणवत्ता को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। बजट में अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के लिए एजेंडा तैयार किया गया है जिसका उद्देश्य उत्पादन बाजारों में समग्र उत्पादकता और दक्षता में सुधार करना है, जो मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं के लिए अच्छा संकेत है।

परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था के कई अनिश्चितताओं से जूझने के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में नौ प्राथमिकताओं के माध्यम से 'विकसित भारत' को प्राप्त करने के लिए एक मध्यम अवधि का रोडमैप तैयार किया गया है, जैसे कि कृषि में उत्पादकता और समुत्थानशीलता, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगली पीढ़ी के सुधार।

बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करने की दिशा में एक 'आर्थिक नीति रूपरेखा' तैयार करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसका उद्देश्य समग्र उत्पादकता में सुधार लाना तथा क्षेत्र और बाजार दक्षता को सुविधाजनक बनाना है। प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों पर जोर देते हुए, बजट में 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्धारित करके सुधारों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।[1]

बजट में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के करों को सरल बनाने का प्रस्ताव किया गया है। व्यापार को आसान बनाने, शुल्क व्युत्क्रमण के लिए हल निकालने और विवादों को कम करने के लिए अगले छह महीनों में सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा करने का प्रस्ताव है। इसने विवादों और मुकदमेबाजी को कम करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की है, जिससे करदाताओं को निश्चितता प्रदान की जा सके। व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर, करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती में वृद्धि के साथ-साथ नई कर व्यवस्था के लिए दर संरचना को संशोधित किया गया है।[2]

व्यय के मोर्चे पर, बुनियादी ढांचे के विकास के मजबूत गुणक प्रभावों को स्वीकार करते हुए, बजट 2024-25 ने पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.1 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) का प्रावधान किया है, जो 2023-24 (अनंतिम खाते, पीए) में आवंटित जीडीपी के 3.2 प्रतिशत से अधिक है। दूसरी ओर, राजस्व व्यय के 2023-24 (पीए) में जीडीपी के 11.8 प्रतिशत से घटकर 2024-25 (बीई) में 11.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

केंद्रीय बजट 2024-25 ने 2024-25 में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को जीडीपी के 4.9 प्रतिशत तक कम करने का बजट बनाकर राजकोषीय विवेक के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया, जो 2025-26 तक जीएफडी को जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे रखने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है। 2026-27 से आगे, बजट ने जीएफडी को उस स्तर पर बनाए रखने के सरकार के इरादे की घोषणा की है जो यह सुनिश्चित करता है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का कर्ज घटता रहेगा।

---

^ यह लेख श्रीमती रेखा मिश्र के समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। लेखक डॉ. नथनएल को उनकी बहुमूल्य टिप्पणियों और सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं। लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

[1] 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण का तात्पर्य केंद्र द्वारा राज्यों को 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के तहत प्रदान किए जाने वाले दीर्घकालिक ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय ऋण से है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, इस योजना के तहत राज्यों को पूंजीगत व्यय सहायता का एक हिस्सा नागरिक केंद्रित सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, 2023-24 में, इस योजना के तहत पूंजीगत व्यय ऋण का एक हिस्सा राज्यों को सुधार केंद्रित और क्षेत्र विशेष क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया गया था, जैसे कि पुराने वाहनों को समाप्त करना, शहरी नियोजन सुधार, शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों का वित्तपोषण करना ताकि उन्हें नगरपालिका बांड के लिए ऋण योग्य बनाया जा सके, पुलिस स्टेशनों के ऊपर या हिस्से के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास, यूनिटी मॉल, 'बच्चों और किशोरों' के लिए पुस्तकालय और डिजिटल बुनियादी ढाँचा।

[2] विस्तृत बजट प्रस्तावों के लिए कृपया अनुबंध III देखें।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख का शेष भाग सात खंडों में विभाजित है। खंड II राजकोषीय घाटे की अंतर्निहित गतिशीलता प्रस्तुत करता है। खंड III और IV क्रमशः केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों का आकलन करते हैं। खंड V केंद्र सरकार की बकाया ऋण स्थिति को दर्शाता है। खंड VI राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों की जांच करता है; जबकि खंड VII राज्यों को संसाधनों के हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करता है। खंड VIII निष्कर्ष संबंधी टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है।

II. राजकोषीय घाटा - अंतर्निहित गतिशीलता

2023-24 के दौरान, सरकार ने विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। केंद्र सरकार का जीएफडी 2023-24 (आरई) में जीडीपी का 5.9 प्रतिशत रहा, जो बजट अनुमान के अनुरूप है। 2023-24 (पीए) के अनुसार, जीएफडी, जीडीपी के 5.6 प्रतिशत पर कम रहा, जो कि गैर-कर प्राप्तियों के साथ-साथ कम राजस्व और पूंजीगत व्यय के कारण 2023-24 (बीई) की तुलना में 32 आधार अंकों की बढ़ोतरी थी [चार्ट 1]। प्राथमिक घाटा 2023-24 (पीए) में जीडीपी का 2.0 प्रतिशत रहा, जबकि बजट अनुमान में यह जीडीपी का 2.3 प्रतिशत था (सारणी 1)।

चार्ट 1: बीई की तुलना में 2023-24 (पीए) में जीएफडी समेकन में योगदान

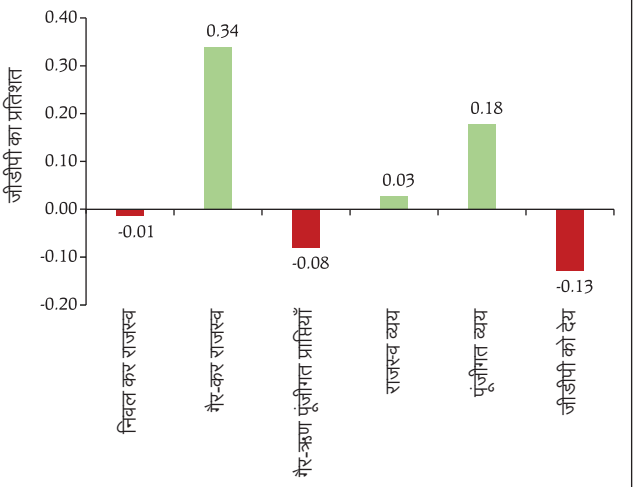

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सारणी 1: प्रमुख संकेतक[3]

(जीडीपी का प्रतिशत)

	2022-23	2023-24			2024-25	
	वास्तविक	बीई	आरई	पीए	बीई (अंतरिम)	बीई (अंतिम)
1	2	3	4	5	6	7
1. राजकोषीय घाटा	6.4	5.9	5.9	5.6	5.1	4.9
2. प्राथमिक घाटा	3.0	2.3	2.3	2.0	1.5	1.4
3. राजस्व घाटा	4.0	2.9	2.8	2.6	2.0	1.8
4. प्रभावी राजस्व घाटा	2.8	1.7	1.8	1.6	0.8	0.6
5. सकल कर राजस्व	11.3	11.1	11.6	11.7	11.7	11.8
6. गैर-कर राजस्व	1.1	1.0	1.3	1.4	1.2	1.7
7. राजस्व व्यय	12.8	11.6	12.0	11.8	11.2	11.4
8. पूंजीगत व्यय	2.7	3.3	3.2	3.2	3.4	3.4
जिसमें से:						
पूंजीगत परिव्यय	*2.3*	*2.8*	*2.7*	*2.7*	*2.9*	*2.8*
9. प्रभावी पूंजीगत व्यय	3.9	4.5	4.3	4.2	4.6	4.6

टिप्पणियां : 1. प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता के बीच का अंतर है।
2. पूंजीगत परिव्यय प्राप्त करने के लिए पूंजीगत व्यय में से ऋण और अग्रिम घटाए गए हैं।
3. प्रभावी पूंजीगत व्यय में पूंजीगत व्यय और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता को जोड़ा गया है।
4. 2023-24 (आरई) के आंकड़े केंद्रीय बजट में प्रस्तुत आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि इनकी गणना 31 मई, 2024 को जारी 2023-24 के लिए जीडीपी के नवीनतम उपलब्ध अनंतिम अनुमानों (₹2,95,35,667 करोड़) का उपयोग करके की गई थी, न कि 01 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट की प्रस्तुति के दौरान उपलब्ध पहले अग्रिम अनुमानों का उपयोग करके।
5. बीई का अर्थ बजट अनुमान है, आरई का अर्थ संशोधित अनुमान है और पीए का अर्थ अनंतिम खाते हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[3] विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक I देखें ।

2024-25 के लिए, जीएफडी को जीडीपी के 4.9 प्रतिशत पर बजट में रखा गया है, जो अंतरिम बजट 2024-25 में जीडीपी के 5.1 प्रतिशत से कम है।[4] 2023-24 (पीए) की तुलना में 2024-25 (बीई) में राजकोषीय सुदृढ़ता को राजस्व व्यय को जीडीपी के 11.4 प्रतिशत तक सीमित करके और राजस्व प्राप्तियों में मजबूत वृद्धि के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की गई है। राजस्व घाटे को 2023-24 (पीए) में जीडीपी के 2.6 प्रतिशत से घटाकर 2024-25 (बीई) में 1.8 प्रतिशत करने का बजट बनाया गया है, जिससे पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय गुंजाइश बनेगी [सारणी 1]।

जीएफडी का अपघटन

राजस्व घाटे (आरडी) द्वारा रोके गए जीएफडी का अनुपात 2018-19 से 2020-21 के दौरान जीएफडी के औसत 73.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 (पीए) में 46.3 प्रतिशत और 2024-25 (बीई) में 36.0 प्रतिशत हो गया है। इसके साथ ही, जीएफडी में वृद्धि-प्रेरक पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 2023-24 (पीए) में बढ़कर 47.6 प्रतिशत हो गया है और 2018-19 से 2020-21 के दौरान जीएफडी के औसत 31.3 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 (बीई) में 56.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है (चार्ट 2)।

III. प्राप्तियां

2023-24 (पीए) में, कुल गैर-ऋण प्राप्तियाँ (निवल कर राजस्व, गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियाँ शामिल हैं) मुख्य रूप से आयकर संग्रह में उछाल के कारण कर राजस्व में मजबूत वृद्धि और रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों से बजट से अधिक अधिशेष/लाभांश प्राप्ति से प्रेरित गैर-कर राजस्व में वृद्धि के कारण 2022-23 की तुलना में 13.6 प्रतिशत बढ़ीं। ऐसी आशा है कि कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के 2024-25 (बीई) में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अपनी गति बनाए रखने की उम्मीद है और 2023-24 (पीए) में 9.4 प्रतिशत से बढ़कर जीडीपी के 9.8 प्रतिशत तक बढ़ने का बजट है।

कर राजस्व

2023-24 (पीए) में सकल कर राजस्व बजट अनुमानों से ₹1.04 लाख करोड़ अधिक रहा। हालांकि, 2023-24 (पीए) में निवल कर राजस्व राज्यों को अधिक कर अंतरण के कारण बजट राशि से थोड़ा कम रहा।[5] 2024-25 के लिए, सकल कर राजस्व में 2023-24 (पीए) की तुलना में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि का बजट है। कर-जीडीपी अनुपात बढ़कर जीडीपी का 11.8 प्रतिशत हो जाएगा, जो 2007-08 के बाद सबसे अधिक है (चार्ट 3)।

चार्ट 2: सकल राजकोषीय घाटे का अपघटन

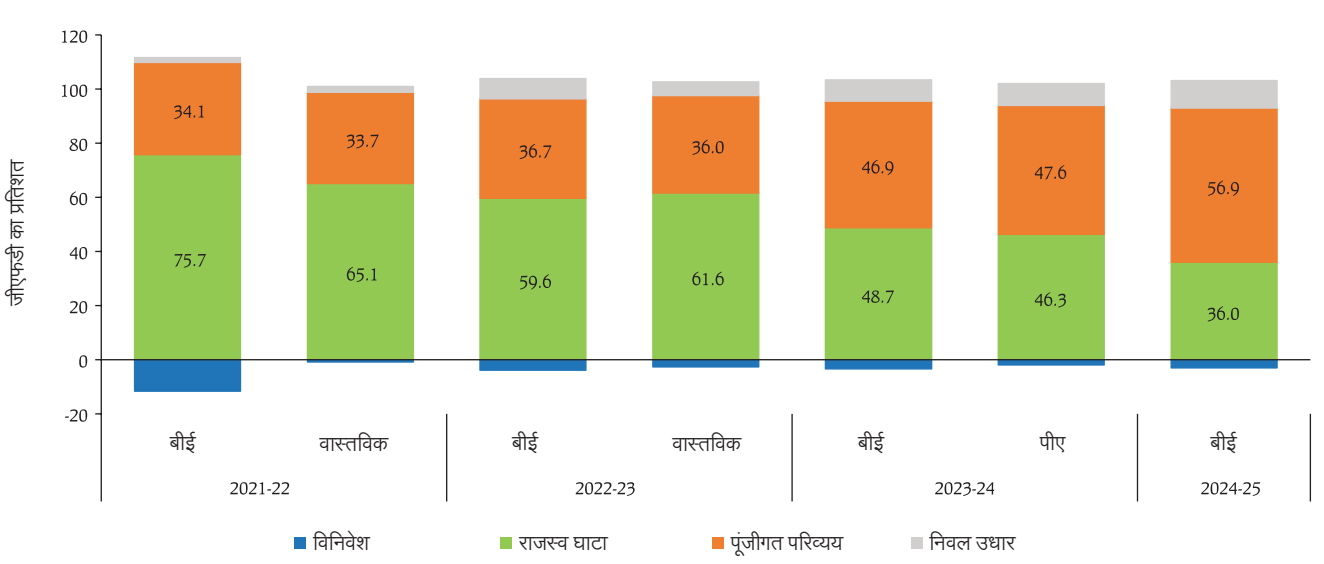

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

[4] 23 जुलाई, 2024 को घोषित अंतिम 2024-25 (बीई) के लिए नाममात्र जीडीपी 3,26,36,912 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है, जो 31 मई, 2024 को एमओएसपीआई द्वारा जारी 2023-24 के जीडीपी के अनंतिम अनुमान (पीई) 2,95,35,667 करोड़ रुपये से 10.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

[5] सकल कर राजस्व में से राज्यों को कर हस्तांतरण घटाकर एनसीसीडी (राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क) निधि में अंतरण।

चार्ट 3: कर-जीडीपी अनुपात

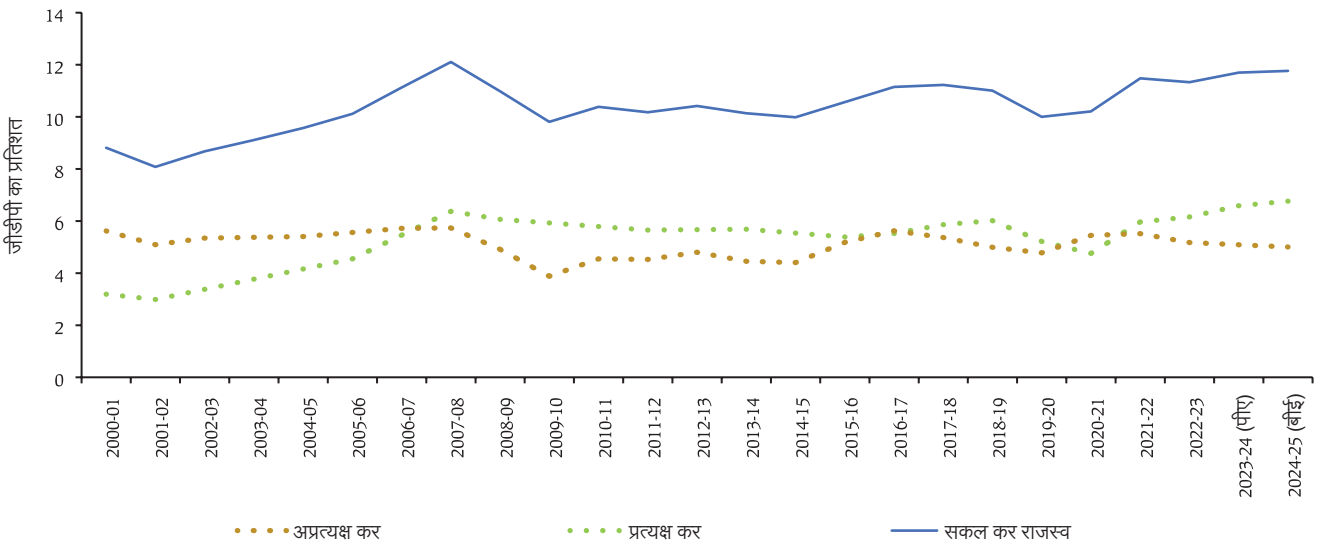

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2024-25 (बीई) के लिए, सकल कर राजस्व का उछाल 1.1 पर 2010-11 से 2018-19 के दौरान अपने औसत के अनुरूप होगा। 2024-25 (बीई) में प्रत्यक्ष करों का उछाल 2023-24 (पीए) की तुलना में कम है, लेकिन औसत प्रवृत्ति से अधिक है। दूसरी ओर, 2024-25 (बीई) में अप्रत्यक्ष करों का उछाल 2023-24 (पीए) की तुलना में अधिक होगा, हालांकि यह औसत प्रवृत्ति (चार्ट 4 ए और बी) से कम रहता है।

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करों ने 2023-24 (पीए) में मजबूत वृद्धि दर्ज की और अपने बजट अनुमानों से ₹1.3 लाख करोड़ अधिक प्राप्त किए, जो आयकर संग्रह में 25.0 प्रतिशत की वृद्धि के कारण बढ़ा। 2024-25 में, प्रत्यक्ष करों में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि का बजट है, जबकि आयकर और निगम कर में क्रमशः 13.8 प्रतिशत और 12.0 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है (चार्ट 5)।

चार्ट 4: कर उछाल का रुझान

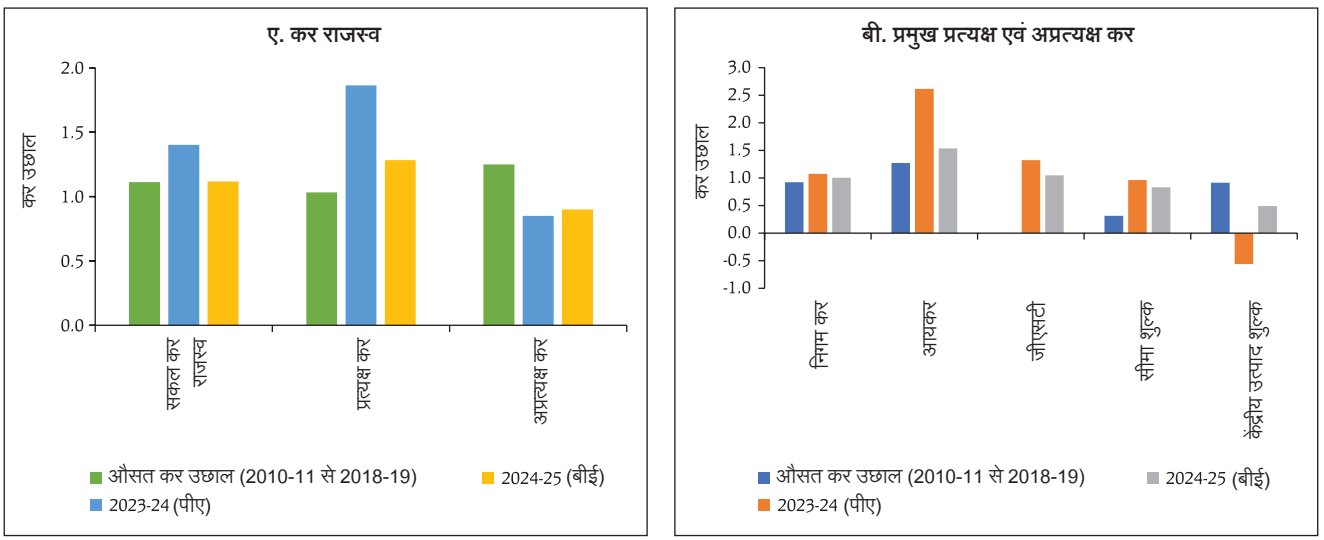

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 5: प्रत्यक्ष कर

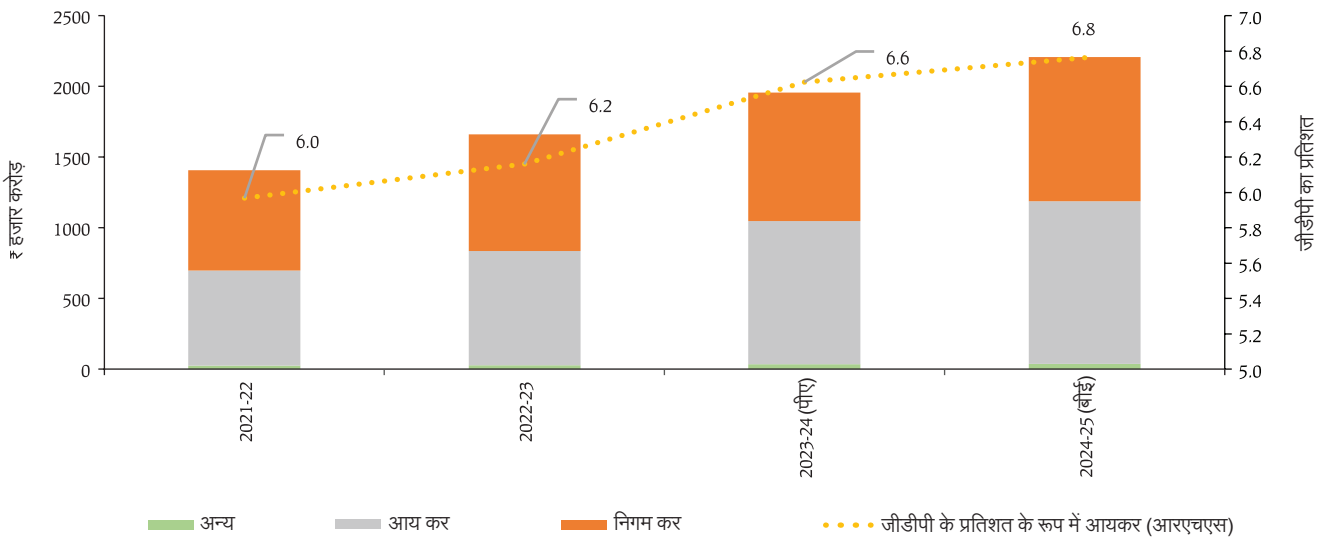

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

बजट में कर निश्चितता में सुधार लाने और कर मुकदमेबाजी को कम करने के साथ-साथ धर्मार्थ कार्यों के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाने, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की संरचना, पूंजीगत लाभ कराधान और आयकर आधार को विस्तारित करने के लिए कदम उठाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर, नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती और पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन को क्रमशः ₹75,000 और ₹25,000 तक बढ़ा दिया गया है, साथ ही नई कर व्यवस्था के तहत कर ढांचे में संशोधन किया गया है; इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹17,500 तक की आयकर बचत होने का अनुमान है। इसके अलावा, सरकार ने बाजार क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ा दिया है (चार्ट 6)।

चार्ट 6: प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)

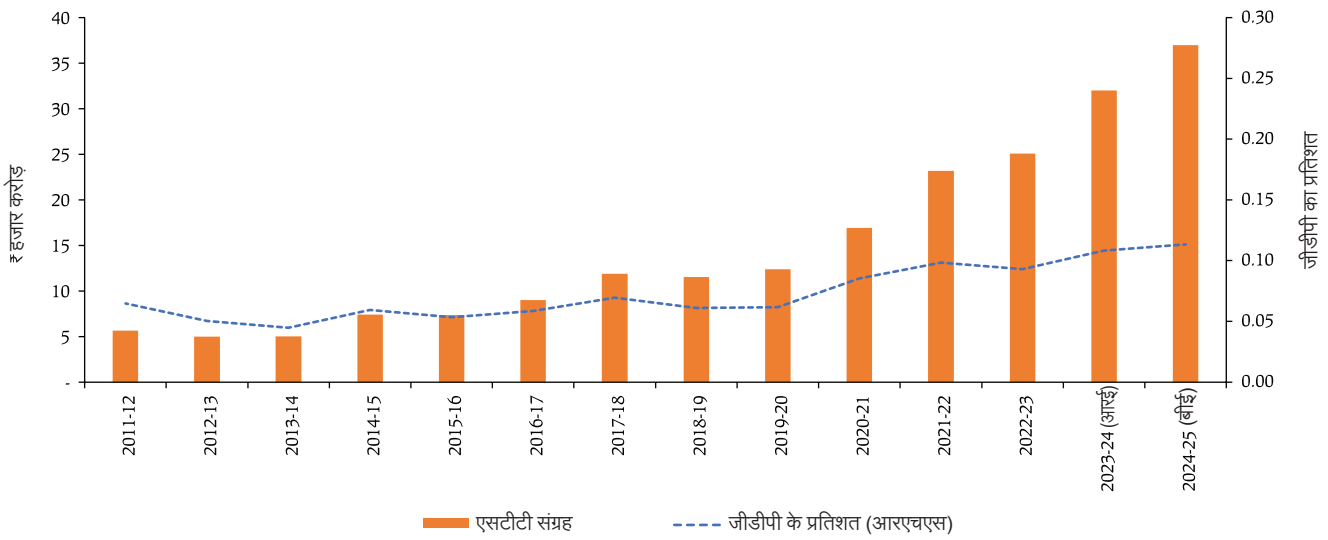

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष कर राजस्व ने 2023-24 (पीए) में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की और मुख्य रूप से केंद्र सरकार के उत्पाद शुल्क संग्रह में ₹33,670 करोड़ की कमी के कारण यह बजट राशि से नीचे आ गया। 2024-25 (बीई) में, अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का बजट 8.3 प्रतिशत है, जिसमें जीएसटी संग्रह (11.0 प्रतिशत), सीमा शुल्क (2.0 प्रतिशत) और उत्पाद शुल्क (6.1 प्रतिशत) प्रमुख है [चार्ट 7]। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ चिकित्सा उपकरणों, मोबाइल फोन, महत्वपूर्ण खनिजों, समुद्री उत्पादों, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कीमती धातुओं, चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए कुछ इनपुट पर सीमा शुल्क में कटौती का प्रस्ताव किया गया है और सौर सेल और पैनल के निर्माण के लिए छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार किया गया है। व्यापार को आसान बनाने, ड्यूटी इन्वर्शन शुल्क को समाप्त करने और विवाद की घटनाओं को कम करने के लिए आने वाले महीनों में सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा करने का भी प्रस्ताव है।

गैर-कर राजस्व

2023-24 (पीए) में गैर-कर प्राप्तियों में 40.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो उनके बजट अनुमान से ₹1.0 लाख करोड़

चार्ट 7: अप्रत्यक्ष कर

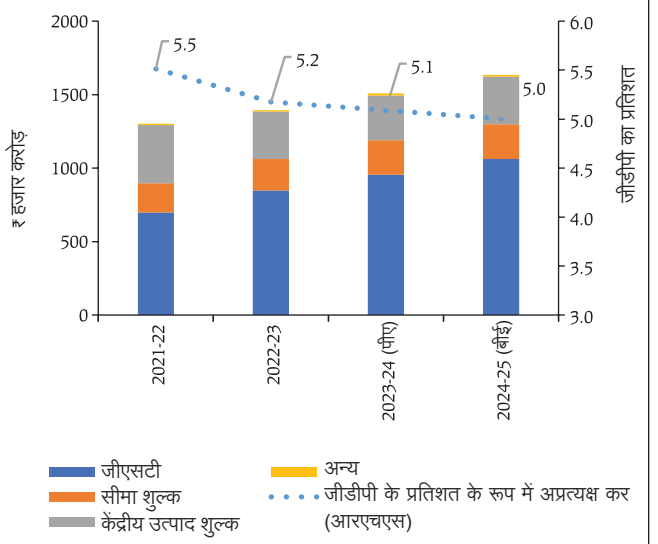

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट 8: गैर-कर राजस्व के प्रमुख घटक

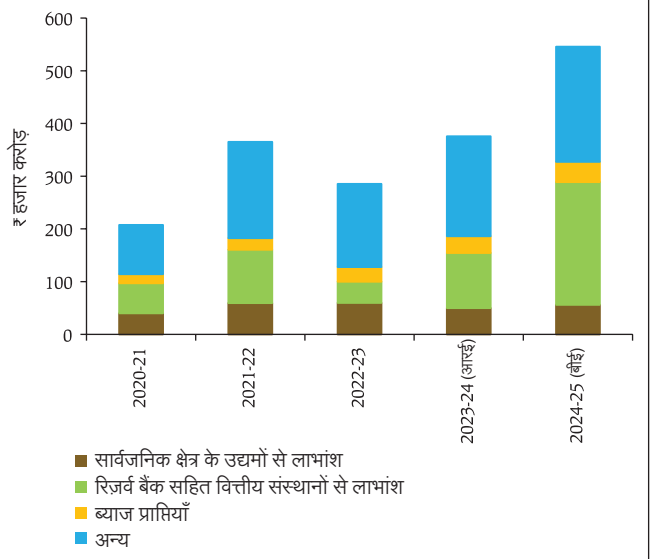

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

अधिक है, जिसका मुख्य कारण रिज़र्व बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा बजट अनुमान से अधिक अधिशेष/लाभांश हस्तांतरण है। 2024-25 (बीई) में, रिज़र्व बैंक द्वारा अधिशेष हस्तांतरण के कारण लाभांश और मुनाफे में वृद्धि के कारण गैर-कर राजस्व में अपनी गति बनाए रखने और 35.8 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है (चार्ट 8)।

गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां

2023-24 (पीए) में, विनिवेश से प्राप्तियों में कमी के कारण गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 16.3 प्रतिशत की गिरावट आई। 2024-25 (बीई) में, गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में 29.0 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें विनिवेश लक्ष्य ₹50,000 करोड़ (चार्ट 9) है।

IV. व्यय

2023-24 (पीए) की तुलना में 2024-25 (बीई) में कुल व्यय में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जबकि 2023-24 (पीए) में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 2024-25 (बीई) में ₹11.1 लाख करोड़ के प्रावधान के साथ पूंजीगत व्यय को जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के दो दशक के उच्च स्तर पर बजट में रखा गया है। राजस्व

चार्ट 9: विनिवेश प्राप्तियाँ - बजट की तुलना में वास्तविक

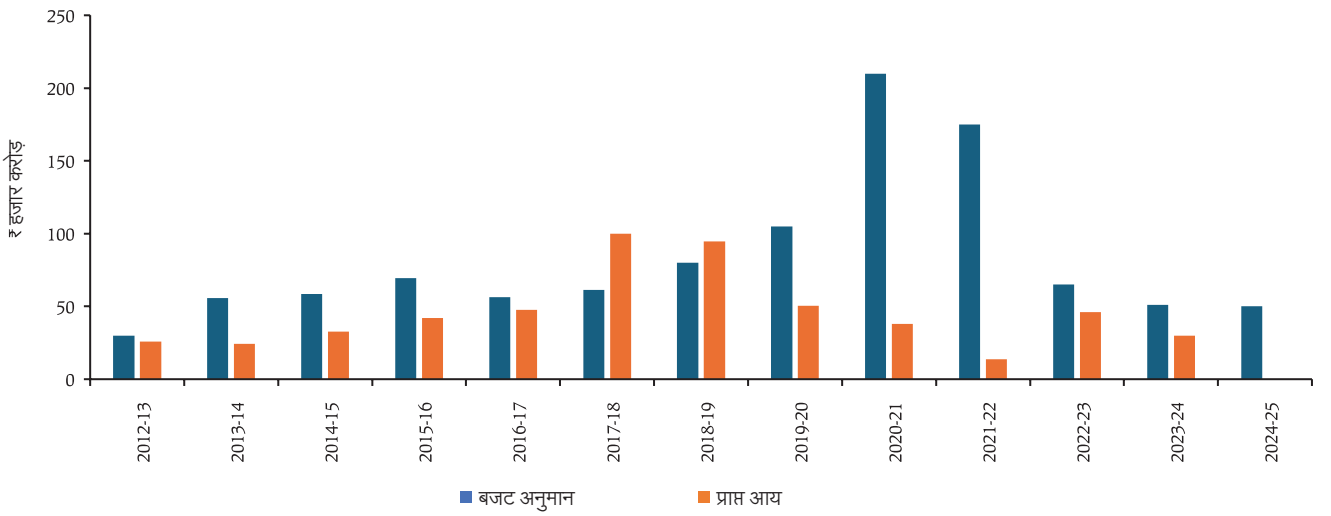

टिप्पणी: 2023-24 (आरई) और 2024-25 (बीई) के लिए विनिवेश प्राप्तियां 'विविध पूंजी प्राप्तियां' शीर्षक के तहत 'प्राप्तियां' को संदर्भित करती हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

व्यय में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है जबकि पूंजीगत व्यय वृद्धि 17.1 प्रतिशत आंकी गई है (सारणी 2)। 2024-25 (बीई) के अनुसार राजस्व व्यय से पूंजीगत परिव्यय अनुपात 4.0 के सर्वकालिक निम्न स्तर पर है, जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार का संकेत है। 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' के लिए परिव्यय को 2023-24 (संशोधित अनुमान) में ₹1.1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2024-25 (बजट अनुमान) में ₹1.5 लाख करोड़ कर दिया गया है [चार्ट 10ए और बी]।

चार्ट 10: केंद्र सरकार का व्यय

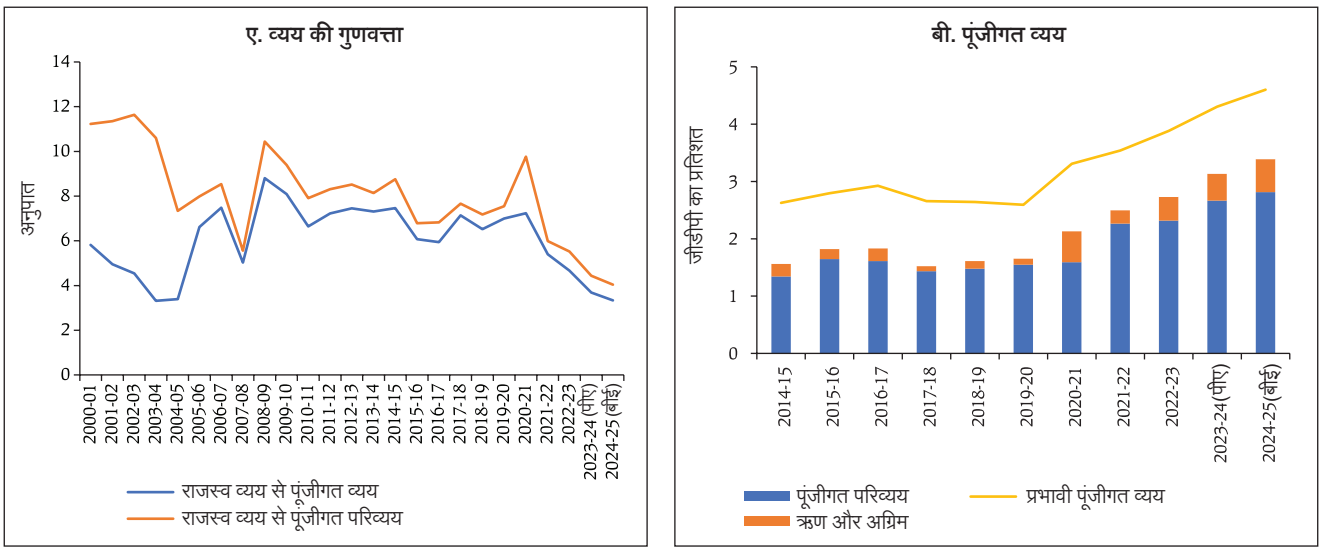

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सारणी 2: केंद्र सरकार का व्यय

मद	₹ हजार करोड़				वृद्धि दर (प्रतिशत)			
	2022-23	2023-24 (आरई)	2023-24 (पीए)	2024-25 (बीई)	2022-23 की तुलना में 2023-24 (आरई)	2022-23 की तुलना में 2023-24 (पीए)	2022-23 (आरई) की तुलना में 2023-24 (बीई)	2022-23 (पीए) की तुलना में 2023-24 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कुल व्यय	4,193	4,490	4,443	4,821	7.1	5.9	7.3	8.5
2. राजस्व व्यय *(जिसमें से)*	3,453	3,540	3,494	3,709	2.5	1.2	4.8	6.2
(i) ब्याज भुगतान	929	1,055	1,064	1,163	13.7	14.6	10.2	9.3
(ii) कुल सब्सिडी	578	441	NA	428	-23.8	NA	-2.7	NA
खाद्य	273	212	212	205	-22.2	-22.4	-3.3	-3.1
उर्वरक	251	189	189	164	-24.8	-24.6	-13.2	-13.5
पेट्रोलियम	7	12	12	12	79.5	79.5	-2.6	-2.6
(iii) एमजीएनआरईजीएस	91	86	NA	86	-5.3	NA	0.0	NA
(iv) पीएम-*किसान*	58	60	NA	60	3.0	NA	0.0	NA
(v) पीएम-*आवास* (ग्रामीण)	45	32	NA	55	-28.8	NA	70.3	NA
(vi) पीएम-*आवास* (शहरी)	29	22	NA	30	-22.9	NA	36.5	NA
(vii) *समग्र शिक्षा*	33	33	NA	38	1.5	NA	13.6	NA
(viii) रक्षा (राजस्व)	256	299	NA	283	16.6	NA	-5.3	NA
3. पूंजीगत व्यय	740	950	949	1,111	28.4	28.2	16.9	17.1
4. प्रभावी पूंजीगत व्यय	1,046	1,271	1,252	1,502	21.5	19.7	18.1	19.9

एनए: उपलब्ध नहीं है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

प्रमुख योजनाओं में, पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम आवास योजना (शहरी), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन[6], सड़क कार्य और समग्र शिक्षा में 2023-24 (संशोधित अनुमान) की तुलना में 2024-25 (बजट अनुमान) में आवंटन में वृद्धि देखी गई है [सारणी 2]।

केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के संयुक्त पूंजीगत व्यय में 2021-22 से वृद्धि देखी गई है, हालांकि सीपीएसई के वित्तपोषण पैटर्न में उलटफेर हुआ है, जहां सीपीएसई के पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए बजटीय सहायता का हिस्सा बढ़ रहा है और आंतरिक संसाधनों और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का हिस्सा कम हो रहा है (बॉक्स ए)।

रेल तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 2024-25 के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय का लगभग आधा हिस्सा खर्च करेंगे (चार्ट 11)। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुल आवंटन 2023-24 (पीए) में सकल घरेलू उत्पाद के 0.03 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 (बीई) में 0.06 प्रतिशत होने का बजट है, जो

चार्ट 11: मंत्रालय-वार पूंजीगत व्यय

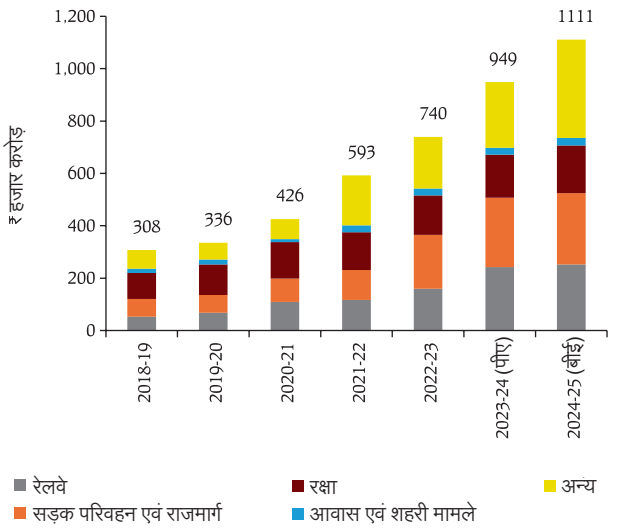

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और लेखा महानियंत्रक (सीजीए)।

[6] राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) तथा स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए सुदृढ़ निधि हेतु आवंटन शामिल है।

बॉक्स ए: पूंजीगत व्यय - सीपीएसई की भूमिका

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)[7] ने भारी उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आगे बढ़ाकर भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[8] सीपीएसई ने घरेलू भौतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहायता की है (रॉय और दास, 2023)। सीपीएसई अपने पूंजीगत व्यय को (i) आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर)[9] और (ii) केंद्र सरकार से प्राप्त बजट समर्थन से वित्तपोषित करते हैं। आईईबीआर के माध्यम से पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादक उद्देश्यों के लिए सरकार के सीमित संसाधनों के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, हालांकि बजटीय समर्थन के माध्यम से सरकार द्वारा सीपीएसई के पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण उधार लेने की समग्र लागत को कम करने में मदद करता है क्योंकि सरकार सीपीएसई की तुलना में कम लागत पर उधार ले सकती है।

केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 2008-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के औसतन 1.7 प्रतिशत से 2021-25 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के 3.0 प्रतिशत तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका दोहरा उद्देश्य घरेलू बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और निजी निवेश को आकर्षित करना है (भारत सरकार, 2023)। अर्थव्यवस्था पर बड़े गुणक प्रभाव वाले सड़क और रेलवे जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। व्यय में वृद्धि केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के साथ-साथ सीपीएसई को प्रदान किए गए बजट समर्थन दोनों में परिलक्षित होती है। हालांकि, सीपीएसई का आईईबीआर कोविड-पूर्व अवधि में 2016-20 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के औसत 2.3 प्रतिशत से घटकर कोविड-पश्चात अवधि (2021-25) में 1.2 प्रतिशत हो गया है।[10] सीपीएसई को दिए जाने वाले बजट समर्थन में वृद्धि और उनके आईईबीआर में कमी के साथ, सीपीएसई के कुल पूंजीगत व्यय में आईईबीआर की हिस्सेदारी कोविड-पूर्व अवधि के औसत 69.9 प्रतिशत से घटकर कोविड-पश्चात अवधि में 46.0 प्रतिशत हो गई है। कुल मिलाकर, केंद्र सरकार और सीपीएसई का कुल पूंजीगत व्यय कोविड-पूर्व अवधि में जीडीपी के औसत 4.0 प्रतिशत से बढ़कर कोविड-पश्चात अवधि में जीडीपी के 4.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट ए.1)।

चार्ट ए.1: केंद्र सरकार और सीपीएसई द्वारा पूंजीगत व्यय

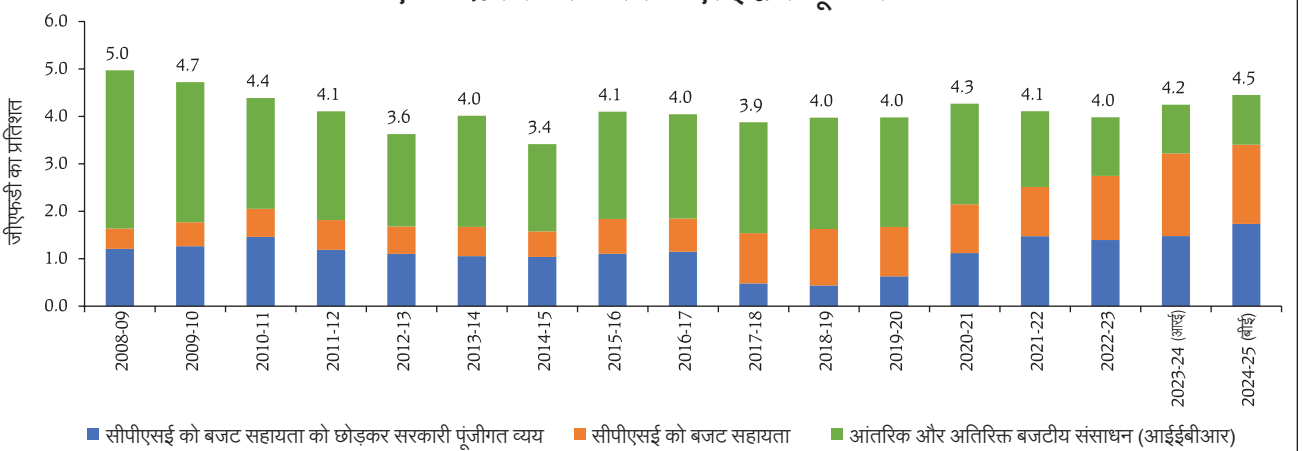

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

References:

1. Government of India (2022). Central Public Sector Enterprises (Protection of Interests of States) Bill, 2022. Rajya Sabha.
2. Roy, S. and Das, S.K. (2023). Public Sector Performance in India and the Ongoing Contestation Between Efficiency and Equity. Institute for Studies in Industrial Development Working Paper 264.
3. Government of India (2023). Monthly Economic Review. Ministry of Finance, June.

[7] सीपीएसई वे कंपनियां हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी पिछले कंपनी कानून के तहत शामिल की गई हैं, या संसद के अधिनियम के अनुसरण में गठित संस्थाएं हैं, जिनमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत शेयर पूंजी केंद्र सरकार या किसी अन्य सीपीएसई या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक सीपीएसई के पास है (भारत सरकार, 2022)।

[8] नवीनतम सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, 402 सीपीएसई हैं, जिनमें से 254 परिचालन कर रहे हैं।

[9] आईईबीआर में आंतरिक संसाधन (सरकार को लाभांश, मूल्यह्रास प्रावधान और रिज़र्व और अधिशेष को आगे ले जाने के बाद अर्जित लाभ शामिल हैं) और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (बांड, डिबेंचर, बाहरी वाणिज्यिक उधार, आपूर्तिकर्ताओं के ऋण, जमा प्राप्तियां और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण जारी करने से प्राप्तियां शामिल हैं) शामिल हैं। बजटीय सहायता और आईईबीआर मिलकर सीपीएसई के पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण करते हैं।

[10] भारतीय खाद्य निगम को इस विश्लेषण से बाहर रखा गया है क्योंकि इसका अधिकांश व्यय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीद पर होता है।

चार्ट 12: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर कुल व्यय

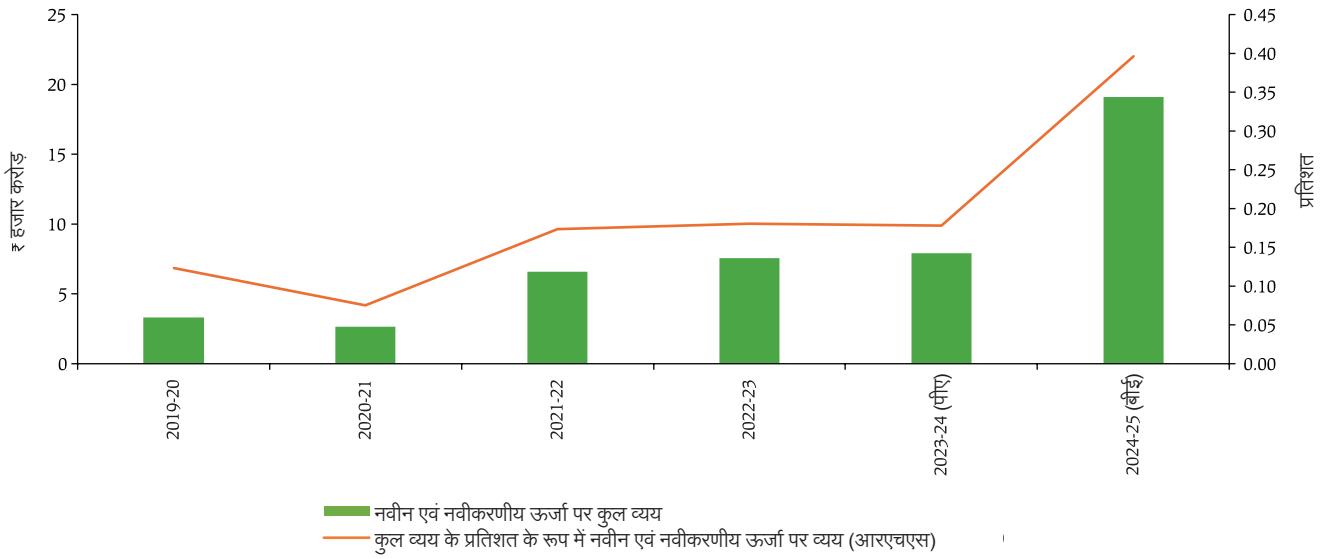

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और सीजीए

सौर ऊर्जा परियोजनाओं (ग्रिड) और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना [11] (चार्ट 12) द्वारा संचालित है। बजट में समावेशी विकास के चार स्तंभों में से एक के रूप में अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जो 2024-25 (बीई) के लिए लिंग बजट आवंटन में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि से परिलक्षित होता है। कुल वृद्धि का आधे से अधिक हिस्सा महिलाओं के कल्याण के लिए 100 प्रतिशत आवंटन वाली योजनाओं के लिए आवंटित किया गया है (चार्ट 13)।

इसके बाद, हम केंद्र सरकार के कुल व्यय को प्रतिबद्ध व्यय (जिसमें स्थापना व्यय[12] , ब्याज भुगतान, वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान और राज्यों को जीएसटी मुआवजा शामिल

चार्ट 13: लैंगिक बजट

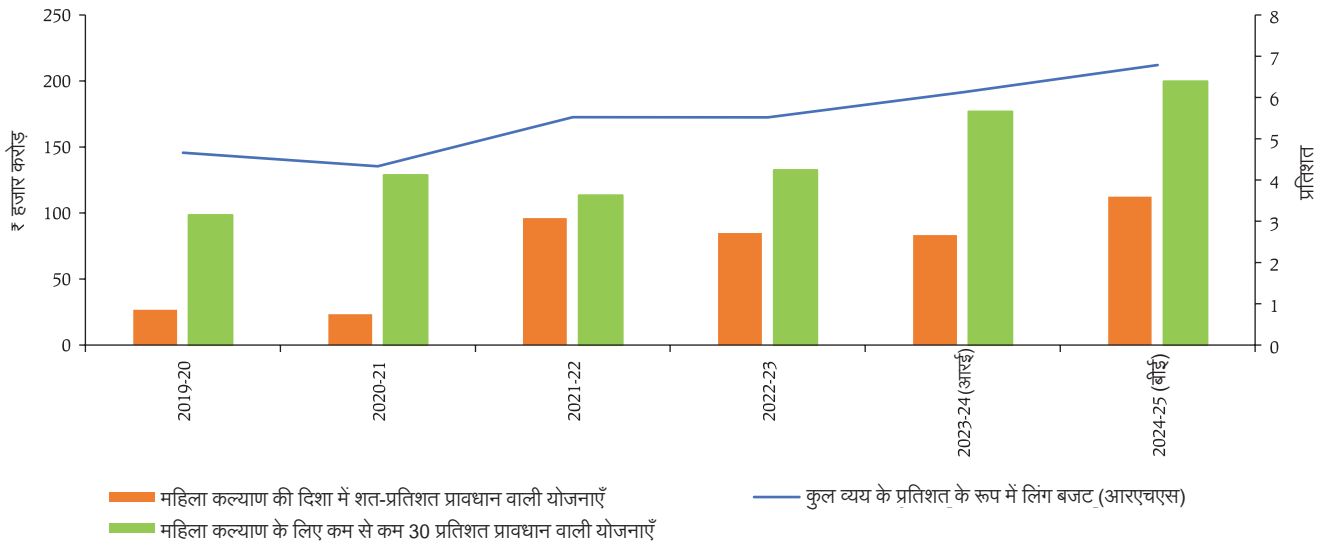

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

[11] पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत के एक करोड़ घरों को मुफ़्त बिजली प्रदान करना है, जो छत पर सौर बिजली इकाई स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं। परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ़्त मिल सकेगी।

[12] स्थापना व्यय में वेतन, मजदूरी, पेंशन और कार्यालय व्यय शामिल हैं।

चार्ट 14: प्रतिबद्ध बनाम विवेकाधीन व्यय

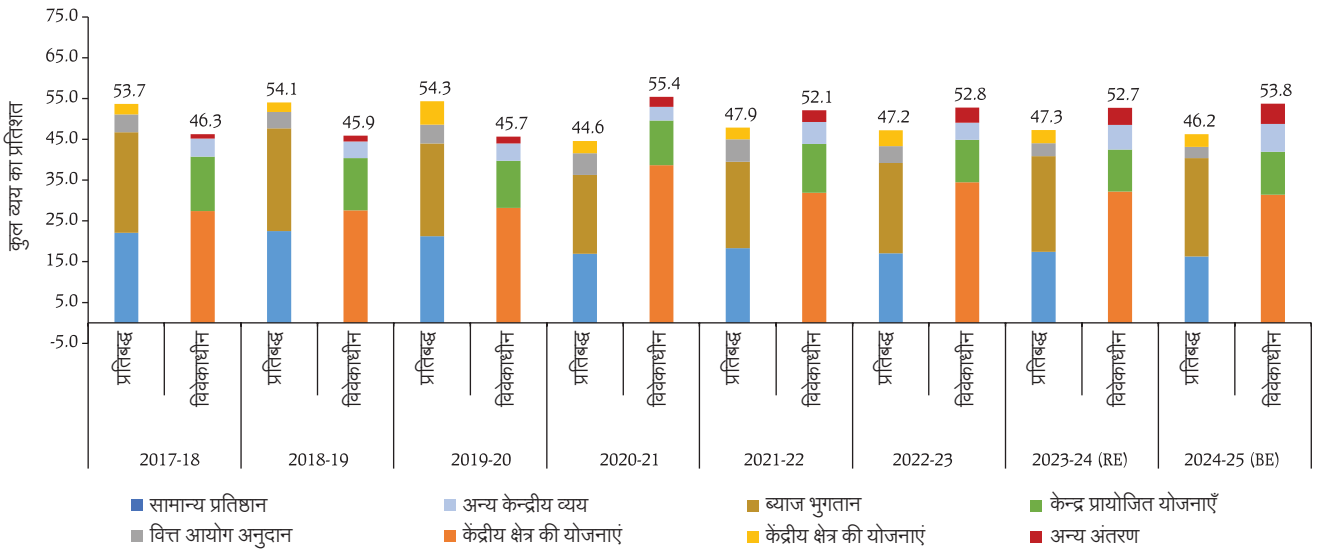

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

है) और विवेकाधीन व्यय [जिसमें केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र प्रायोजित योजनाएं और राज्यों को हस्तांतरण (वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी मुआवजा को छोड़कर) शामिल हैं] में विभाजित करते हैं। महामारी से पहले, प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा विवेकाधीन व्यय से अधिक था। हालांकि, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देने और सामान्य स्थापना पर व्यय के हिस्से में कमी के साथ, प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2024-25 (बीई) में कुल व्यय का 46.2 प्रतिशत रह गया है [चार्ट 14]।

बजट में जलवायु अनुकूलन और शमन से संबंधित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध पूंजी को बढ़ाने के लिए जलवायु वित्तपोषण के लिए वर्गीकरण विकसित करने का प्रस्ताव है। यह भारत की जलवायु और हरित प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने में भी मदद करेगा। हाल ही में, कुछ देशों ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जलवायु बजट टैगिंग (सीबीटी) की प्रथा को अपनाया है (बॉक्स बी)।

बॉक्स बी: जलवायु बजट टैगिंग - चुनिंदा देश के अनुभव

जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है, जिसमें ऊर्जा, वन, जल, कृषि, लोक निर्माण और अन्य मंत्रालय/विभाग जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के उद्देश्य से व्यय करने की ज़िम्मेदारी साझा करते हैं। पारंपरिक बजट विधियाँ अंतर-क्षेत्रीय व्यय को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित नहीं हैं, और जलवायु बजट टैगिंग (सीबीटी) इस समस्या के समाधान के रूप में सामने आई है। हाल के वर्षों में, देशों ने सूचित नीतिगत निर्णय और संसाधन आवंटन (ओईसीडी, 2021) करने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित व्यय को टैग करने में रुचि दिखानी शुरू कर दी है। सीबीटी सरकार की बजट प्रणाली में जलवायु-संबंधित व्यय की पहचान, वर्गीकरण, भार और चिह्नांकन करने का एक उपकरण है, जिससे ऐसे व्यय का अनुमान, ट्रैकिंग और निगरानी करना संभव हो जाता है (यूएनडीपी, 2019)। सीबीटी के विकास और कार्यान्वयन की प्रक्रिया को चार्ट बी.1 में संक्षेप में बताया गया है।

2022 तक, 26 देशों ने केंद्रीय सरकार के स्तर पर सीबीटी की शुरुआत की है या इसका संचालन किया है। विभिन्न देशों द्वारा उनके स्थानीय संदर्भों, राजनीतिक संरचना, साथ ही संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर सीबीटी के लिए विविध दृष्टिकोण लागू किए गए हैं। इंडोनेशिया, केन्या, फ्रांस, आयरलैंड और इथियोपिया जैसे देशों ने जलवायु प्रासंगिक व्यय को परिभाषित करने के लिए उद्देश्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें जलवायु-प्रासंगिक गतिविधियों को उनके इच्छित प्रभाव के आधार पर प्रतिष्ठित किया जाता है। सीबीटी का कवरेज इंडोनेशिया, बांग्लादेश और इथियोपिया में चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित है, जबकि

(जारी)

चार्ट बी.1: जलवायु बजट टैगिंग के विकास और कार्यान्वयन की प्रक्रिया

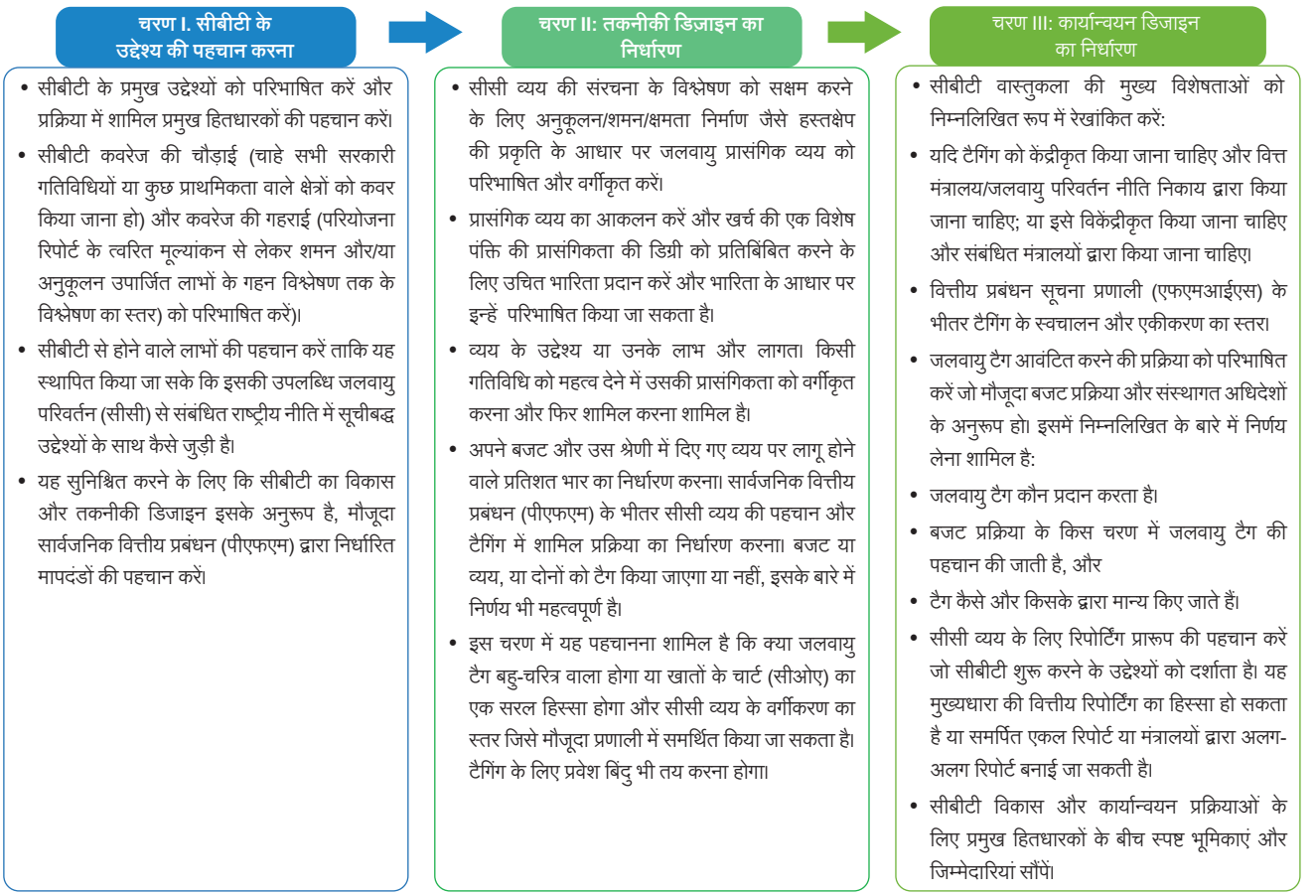

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)।

इसे मेक्सिको, फ्रांस, आयरलैंड, केन्या, नेपाल और फिलीपींस (विश्व बैंक, 2021) में सभी क्षेत्रों तक बढ़ाया गया है।

जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाकर, सीबीटी केंद्रीय वित्त और लाइन एजेंसियों में जलवायु संबंधी विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।[13] सीबीटी में प्राथमिक चुनौती जलवायु प्रासंगिक व्यय के कार्यात्मक क्षेत्रों को परिभाषित करने और उनका परिसीमन करने से संबंधित है। जलवायु प्रासंगिक व्यय को भारिता निर्धारित करने का कोई मानक तरीका भी नहीं है, जो अंतर-देशीय विश्लेषण को कठिन बनाता है। सीबीटी प्रक्रिया में एक और चुनौती कणीय टैगिंग की इच्छा को संतुलित करना है जो सरकार की क्षमता और संसाधनों के साथ अधिक सटीकता प्रदान करती है। बजट टैगिंग प्रक्रिया व्यक्तिपरकता हो सकती है, समावेशन और बहिष्करण त्रुटियों से ग्रस्त हो सकती है और परियोजनाओं की 'ग्रीनवाशिंग [14]' की अनुमति दे सकती है। टैगिंग प्रक्रिया पर स्पष्ट मार्गदर्शन के साथ-साथ प्रक्रिया की आंतरिक पूर्व-पश्चात जाँच और टैग किए गए कार्यक्रमों के प्रदर्शन जाँच इन चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं (ओईसीडी, 2021)। सीबीटी केवल किए गए व्यय की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इसकी प्रभावशीलता या प्राप्त परिणामों के बारे में नहीं (विश्व बैंक, 2021)।

References:

1. OECD. (2021). Green Budget Tagging: Introductory Guidance & Principles.
2. UNDP. (2019). Knowing What You Spend: A Guidance Note for Governments to Track Climate Finance in their Budgets.
3. World Bank. (2021). Climate Change Budget Tagging: A Review of International Experience.

[13] उदाहरण के लिए, फिलीपींस में सीबीटी और संबंधित सुधारों के कार्यान्वयन से बजट प्रक्रिया में जलवायु परिवर्तन को मुख्यधारा में लाने में मदद मिली है और इसके परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय बजट का आवंटन 2018 से 2024 के दौरान 10.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।

[14] किसी गतिविधि/कार्यक्रम के पर्यावरणीय प्रदर्शन को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि अधिक सकारात्मक तस्वीर पेश करने के लिए उसके पर्यावरणीय लाभों के संबंध में जनता/उपभोक्ताओं को गुमराह किया जा सके।

V. बकाया ऋण

कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 62.7 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद, केंद्र सरकार का कुल बकाया ऋण 2024-25 (बीई) में सकल घरेलू उत्पाद के 56.8 प्रतिशत तक गिरने का अनुमान है। ब्याज भुगतान - राजस्व प्राप्ति अनुपात 2023-24 (आरई) में 39.1 प्रतिशत से घटकर 2024-25 (बीई) में 37.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। ऋण स्थिरता का एक संकेतक, ब्याज दर वृद्धि अंतर (आईआरजीडी) अनुकूल बना हुआ है। ऋण समेकन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, 2026-27 से, सरकार का लक्ष्य प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे को इस तरह रखना है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का ऋण घटता रहेगा (चार्ट 15ए और बी)।

VI. सकल राजकोषीय घाटा वित्तपोषण

2024-25 (बीई) में, जीएफडी को जीडीपी के 4.9 प्रतिशत पर बजट में रखा गया है, जो 2023-24 (पीए) में जीडीपी के 5.6 प्रतिशत से कम है। राजकोषीय घाटे की गतिशीलता पर नज़र रखते हुए, 2024-25 (बीई) में केंद्र सरकार की निवल और सकल बाजार उधारी को 2023-24 (आरई) के साथ-साथ अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित राशि से कम रखा गया है। केंद्र सरकार के लिए जीएफडी के वित्तपोषण का मुख्य स्रोत बाजार उधारी है, इसके बाद छोटी बचत के बदले जारी की गई प्रतिभूतियाँ हैं। दिनांकित प्रतिभूतियों (टी-बिलों को छोड़कर) के माध्यम से निवल बाजार उधारी से 2023-24 (संशोधित अनुमान) में 68.0 प्रतिशत की तुलना में 2024-25 (बजट अनुमान) में जीएफडी का 72.1 प्रतिशत वित्तपोषित होने की उम्मीद है, जबकि लघु बचत (एनएसएसएफ) (₹4.20 लाख करोड़) से 2024-25 (बजट अनुमान) में जीएफडी का 26.0 प्रतिशत वित्तपोषित होगा (2023-24 में ₹4.71 लाख करोड़) [चार्ट 16]।

चार्ट 16: सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

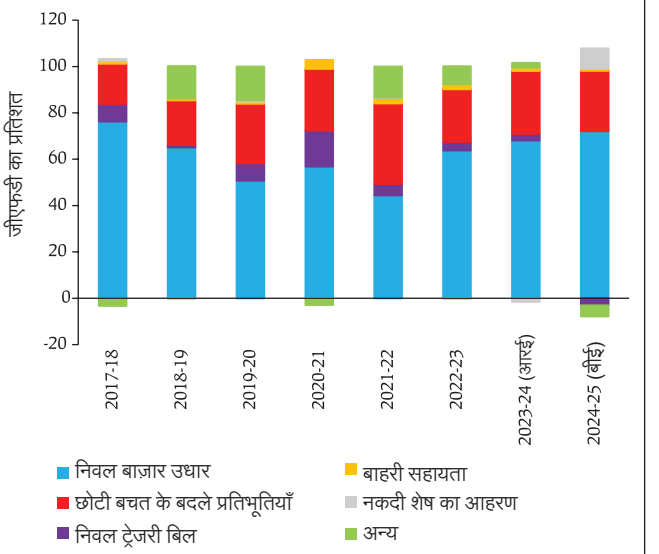

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

चार्ट 15: बकाया देयताओं और ब्याज दर वृद्धि अंतर

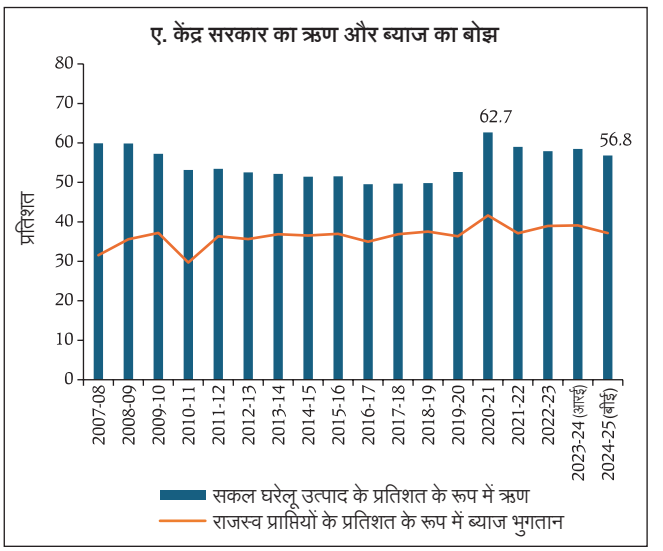

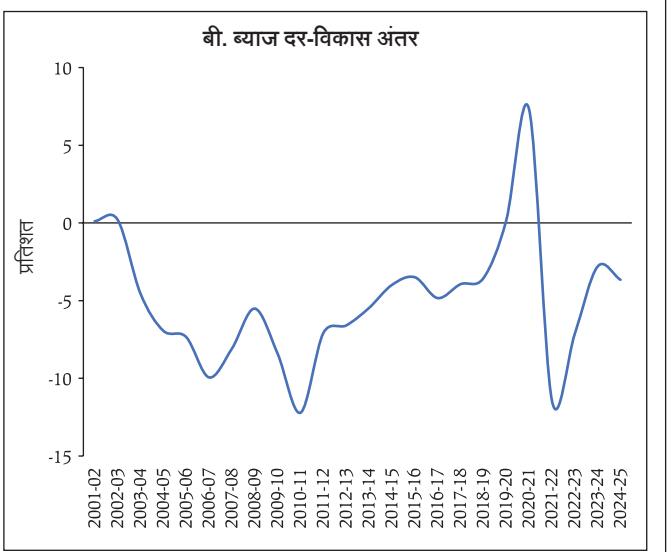

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सारणी 3: केंद्र सरकार की बाजार उधारी

(₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	सकल बाजार उधारी	निवल बाजार उधारी
2018-19	5,71,000 (3.0)	4,22,735 (2.2)
2019-20	7,10,000 (3.5)	4,73,968 (2.4)
2020-21	12,60,116 (6.3)	10,32,907 (5.2)
2021-22	9,68,382 (4.1)	7,04,097 (3.0)
2022-23	14,21,000 (5.3)	11,08,259 (4.1)
2023-24 (आरई)	15,43,000 (5.2)	11,80,456 (4.0)
2024-25 (बीई)	14,01,000 (4.3)	11,63,181 (3.6)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के अनुसार हैं।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

केंद्र सरकार की बाजार उधार आवश्यकताओं (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में) को धीरे-धीरे महामारी-पूर्व स्तर तक कम करने से निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित होगी (सारणी 3)।

VII. केंद्र से राज्यों को संसाधन हस्तांतरण

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सकल हस्तांतरण में 2023-24 (संशोधित अनुमान) में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जो उच्च कर हस्तांतरण, पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत हस्तांतरण के कारण है (चार्ट 17ए और बी)। तदनुसार, सकल घरेलू उत्पाद में सकल हस्तांतरण अनुपात 2023-24 में 7.1 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 7.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है।[15]

वित्त आयोग अनुदान में 2024-25 (बजट अनुमान) में 5.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जिसका मुख्य कारण हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान में कमी है [16] (सारणी 4)।

2024-25 के केंद्रीय बजट में, केंद्र सरकार ने पूर्वी राज्यों - बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से पूर्वोदय योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। यह पहल मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढाँचे में वृद्धि और आर्थिक अवसर सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगी,

चार्ट 17: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सकल संसाधन हस्तांतरण

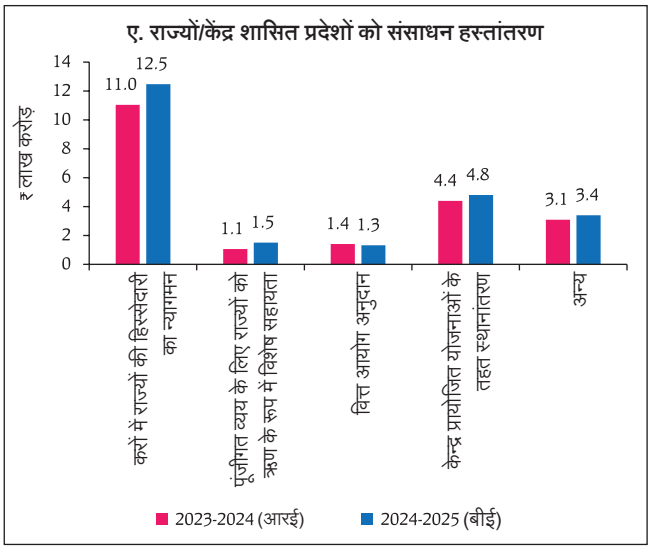

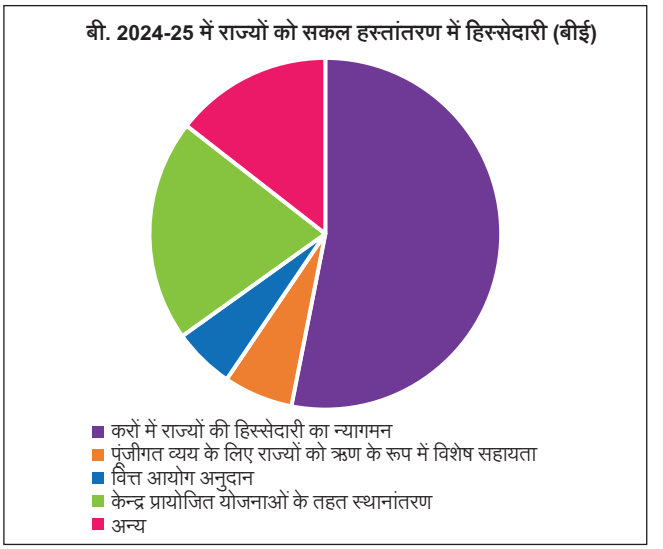

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

[15] विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अनुलग्नक II देखें।

[16] संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किए जाते हैं।

सारणी 4: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्त आयोग (एफसी) अनुदान

	₹ लाख करोड़		कुल एफसी अनुदान में हिस्सेदारी (प्रतिशत)		वृद्धि (प्रतिशत)	
	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)
वित्त आयोग (एफसी) अनुदान	1.40	1.32	100.0	100.0	-18.7	-5.7
1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - शहरी निकाय	0.19	0.26	13.7	19.4	8.1	33.5
2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय	0.41	0.50	29.0	37.6	-10.5	22.1
3. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	0.04	0.06	2.8	4.5	20.9	50.1
4. न्यागमन के बाद राजस्व घाटा अनुदान	0.52	0.24	36.8	18.5	-40.1	-52.6
5. अन्य	0.25	0.26	17.6	20.0	24.4	6.8

टिप्पणी: अन्य में नए शहरों के उद्भव के लिए अनुदान, साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान, एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए सहायता अनुदान शामिल हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र को विकसित भारत के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में बदलना है। 2024-25 के लिए, राज्यों को समर्थन देने के लिए दीर्घकालिक, ब्याज मुक्त ऋण के लिए ₹1.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष के ₹1.1 लाख करोड़ से अधिक है।[17]

केंद्र सरकार राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर 100 शहरों में या उसके आसपास पूर्ण अवसंरचना से सुसज्जित 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए काम करेगी। इसके लिए नगर नियोजन योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। केंद्र और राज्य दोनों ही आर्थिक और पारगमन नियोजन के माध्यम से 'शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने' पर सहयोग करेंगे, जिससे नगर नियोजन योजना का उपयोग करके पेरी-अर्बन क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा।

इसके अतिरिक्त, केंद्र, राज्यों के सहयोग से, कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल को लागू करेगा, जिसका लक्ष्य तीन वर्षों के भीतर 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण पंजीकृत करना है। उच्च स्टाम्प शुल्क वाले राज्यों को दरों को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए, क्योंकि यह सुधार शहरी विकास योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। राज्यों को व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य सरकारों और उद्योग के साथ साझेदारी में विकसित कौशल के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना की घोषणा की जाएगी।

VIII. निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2024-25 का उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करना है, साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का दोहन करना है। युवाओं के लिए रोजगार और रोजगार के अवसरों में सुधार लाने के उद्देश्य से कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है, जिसमें राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए आवंटन और निरंतर समर्थन बढ़ाया गया है। केंद्र ने 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे जीएफडी के अपने मध्यम अवधि के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 2026-27 से आगे, बजट ने सकल राजकोषीय घाटे को उस स्तर पर बनाए रखने के अपने निश्चय की घोषणा की है जो यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार का कर्ज जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घटता रहेगा। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2024-25 राजकोषीय विवेक और समष्टि-आर्थिक स्थिरता के बीच सही संतुलन बनाता है, जिससे मध्यम अवधि के विकास के दृष्टिकोण को मजबूती मिलनी चाहिए।

[17] 50 वर्ष की अवधि के ब्याज मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी से संबंधित सुधारों के तीव्र कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किया जाएगा।

अनुबंध I - केंद्रीय बजट 2024-25: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

	₹ हजार करोड़				जीडीपी का प्रतिशत		वृद्धि दर	
	2022-23	2023-24 (आरई)	2023-24 (पीए)	2024-25 (बीई)	2023-24 (पीए)	2024-25 (बीई)	2022-23 की तुलना में 2023-24 (पीए)	2023-24 (पीए) की तुलना में 2024-25 (बीई)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. प्रत्यक्ष कर	1,660	1,945	1,957	2,207	6.6	6.8	17.9	12.8
(i) निगम	826	923	911	1,020	3.1	3.1	10.3	12.0
(ii) आय	809	990	1,011	1,150	3.4	3.5	25.0	13.8
2. अप्रत्यक्ष कर	1,394	1,492	1,508	1,633	5.1	5.0	8.2	8.3
(i) जीएसटी	849	957	957	1,062	3.2	3.3	12.7	11.0
(ii) सीमा शुल्क	213	219	233	238	0.8	0.7	9.2	2.0
(iii) उत्पाद शुल्क	323	308	305	324	1.0	1.0	-5.4	6.1
3. सकल कर राजस्व (1+2)	3,054	3,437	3,465	3,840	11.7	11.8	13.4	10.8
4. राज्यों को समनुदेशन	948	1,104	1,129	1,247	3.8	3.8	19.1	10.4
5. एनसीसीडी अंतरण	8	9	9	9	0.0	0.0	9.7	7.8
6. निवल कर राजस्व (3-4-5)	2,098	2,324	2,327	2,583	7.9	7.9	10.9	11.0
7. गैर-कर राजस्व	285	376	402	546	1.4	1.7	40.8	35.8
(i) लाभांश और लाभ	100	154	170	289	0.6	0.9	70.6	69.6
(ii) ब्याज प्राप्तियां	28	32	38	38	0.1	0.1	37.5	-0.2
8. राजस्व प्राप्तियां (6+7)	2,383	2,700	2,728	3,129	9.2	9.6	14.5	14.7
9. गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	72	56	60	78	0.2	0.2	-16.3	29.0
(i) विविध पूंजी प्राप्तियां	46	30	33	50	0.1	0.2	-28.1	51.0
(ii) ऋणों की वसूली	26	26	27	28	0.1	0.1	4.5	2.4
10. कुल प्राप्तियां (उधार को छोड़कर) (8+9)	2,455	2,756	2,789	3,207	9.4	9.8	13.6	15.0
11. राजस्व व्यय	3,453	3,540	3,494	3,709	11.8	11.4	1.2	6.2
(i) ब्याज भुगतान	929	1,055	1,064	1,163	3.6	3.6	14.6	9.3
(ii) कुल सब्सिडी	578	441	NA	428	NA	1.3	NA	NA
खाद्य	273	212	212	205	0.7	0.6	-22.4	-3.1
उर्वरक	251	189	189	164	0.6	0.5	-24.6	-13.5
पेट्रोलियम	7	12	12	12	0.0	0.0	79.5	-2.6
12. पूंजीगत व्यय (i + ii)	740	950	949	1,111	3.2	3.4	28.2	17.1
(i) पूंजीगत परिव्यय	625	807	787	919	2.7	2.8	26.0	16.7
(ii) ऋण और अग्रिम	115	143	161	192	0.5	0.6	39.8	19.4
13. कुल व्यय (11+12)	4,193	4,490	4,443	4,821	15.0	14.8	5.9	8.5
14. सकल राजकोषीय घाटा (13-10)	1,738	1,735	1,654	1,613	5.6	4.9	-4.8	-2.4

एनए: उपलब्ध नहीं है।
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

अनुबंध II: केंद्र से राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों को संसाधन हस्तांतरण

		₹ हजार करोड़			सकल हस्तांतरण का प्रतिशत			वृद्धि दर		
		2022-23	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)	2022-23	2023-24 (आरई)	2024-25 (बीई)	2021-22 की तुलना में 2022-23	2022-23 की तुलना में 2023-24 (आरई)	2023-24 (आरई) की तुलना में 2024-25 (बीई)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	करों में राज्यों के हिस्से का न्यागमन	948.4	1,104.5	1,247.2	50.9	52.6	53.1	5.6	16.5	12.9
II	वित्त आयोग अनुदान		140.4	132.4	9.3	6.7	5.6	-16.7	-18.7	-5.7
	जिनमें से:									
	1. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - शहरी निकाय	17.8	19.2	25.7	1.0	0.9	1.1	10.1	8.1	33.5
	2. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान - ग्रामीण निकाय	45.6	40.8	49.8	2.4	1.9	2.1	13.1	-10.5	22.1
	3. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान	3.3	4.0	6.0	0.2	0.2	0.3	-73.0	20.9	50.1
	4. एसडीआरएफ के लिए सहायता अनुदान	16.4	19.6	20.6	0.9	0.9	0.9	-7.6	19.4	5.0
	5. राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए सहायता अनुदान	3.5	4.9	5.1	0.2	0.2	0.2	38.6	39.8	5.0
	6. न्यागमन के बाद राजस्व घाटा अनुदान	86.2	51.7	24.5	4.6	2.5	1.0	-27.2	-40.1	-52.6
III	हस्तांतरण की कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं	120.4	161.0	224.6	6.5	7.7	9.6	-40.7	33.7	39.5
	जिनमें से:									
	1. बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं-ऋण	28.2	29.5	33.9	1.5	1.4	1.4	22.1	4.7	14.9
	2. पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	81.2	105.6	150.0	4.4	5.0	6.4	472.4	30.0	42.1
	3. मांग के तहत विशेष सहायता - राज्यों को अंतरण	2.3	13.0	20.0	0.1	0.6	0.9	-39.7	472.4	53.8
IV	राज्यों को कुल हस्तांतरण [I+II+III के अलावा]	566.9	636.3	686.9	30.4	30.3	29.2	63.9	12.2	8.0
	1. केंद्र प्रायोजित योजनाएं (राजस्व)	405.9	439.3	479.6	21.8	20.9	20.4	21.3	8.2	9.2
	2. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (राजस्व)	12.9	64.2	63.4	0.7	3.1	2.7	28.7	398.7	-1.3
	3. व्यय की अन्य श्रेणियां (राजस्व)	148.1	132.7	143.9	7.9	6.3	6.1	..	-10.4	8.4
	4. पूंजी हस्तांतरण	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	..	2.0
V	दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर को अंतरण	56.2	56.8	57.8	3.0	2.7	2.5	9.9	1.0	1.8
VI	राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को सकल अंतरण (I+II+III+IV+V)	1,864.6	2,099.0	2,349.0	100.0	100.0	100.0	9.3	12.6	11.9
VII	ऋण और अग्रिम की कम वसूली	10.1	25.3	50.3	0.5	1.2	2.1	-42.4	149.7	99.0
VIII	निवल अंतरण (VI-VII)	1,854.5	2,073.7	2,298.7	99.5	98.8	97.9	9.9	11.8	10.9
IX	सकल अंतरण / जीडीपी (प्रति वर्ष) प्रतिशत)	6.9	7.1	7.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA
X	निवल अंतरण / जीडीपी (प्रतिशत)	6.9	7.0	7.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA

एनए: लागू नहीं। '..': कम आधार के कारण असामान्य वृद्धि।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज।

अनुबंध III: केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

बजट में नौ प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। इन नौ प्राथमिकताओं के लिए कुछ प्रमुख प्रस्ताव और बजट में घोषित कर प्रस्तावों की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और समुत्थानशीलता

- कृषि उत्पादकता बढ़ाने और फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान ढांचे की व्यापक समीक्षा की जाएगी।
- किसानों और उनकी भूमि के पंजीकरण के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू की जाएगी। इस वर्ष खरीफ के लिए 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा।
- ग्रामीण विकास को गति देने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए एक व्यापक 'राष्ट्रीय सहकारिता नीति' जारी की जाएगी। इससे सहकारी क्षेत्र का सुव्यवस्थित तथा समग्र विकास भी सुनिश्चित होगा।

प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल

- 'रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन' के अंतर्गत सरकार तीन योजनाएं शुरू करेगी, अर्थात, सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना; विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफओ अंशदान के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन; तथा सभी क्षेत्रों में नियुक्त अतिरिक्त कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के ईपीएफओ अंशदान की प्रतिपूर्ति।
- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास से संबंधित सुधार, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए बेहतर बाजार पहुंच, उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों की स्थापना और क्रेच की स्थापना की जाएगी।
- सरकार उद्योग की मांगों को पूरा करते हुए युवाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। इसके लिए वह 1000 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत ऋण की राशि में वृद्धि, तथा किसी अन्य योजना के तहत सम्मिलित नहीं किए गए युवाओं के लिए घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान जैसे उपायों को लागू करेगी।

प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

- सरकार पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड-अप इंडिया जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी।
- जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को व्यापक दृष्टिकोण के साथ शुरू किया जाएगा।

प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएँ

- एमएसएमई के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की जाएगी, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई को 100 करोड़ रुपये तक का गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें बिना किसी जमानत या तीसरे पक्ष की गारंटी के मशीनरी और उपकरण खरीदने में सुविधा होगी। इसके अलावा, उन उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत अपने पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है।
- युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए, प्रति माह ₹5,000 का इंटर्नशिप भत्ता और ₹6,000 की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। कंपनियों को इंटर्नशिप लागत को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

प्राथमिकता 5: शहरी विकास

- राज्यों और बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी से सरकार 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं को बढ़ावा देगी।
- जिन राज्यों में स्टाम्प शुल्क अधिक है, उन्हें इसे कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए इसे और भी कम किया जाएगा।

प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा

- विकसित भारत के लिए समग्र ऊर्जा मिश्रण में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए, सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी ताकि (क) भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, (ख) भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास, और (ग) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सके।
- 60 क्लस्टरों में पारंपरिक सूक्ष्म और लघु उद्योगों का निवेश-स्तर का ऊर्जा लेखा-परीक्षण किया जाएगा तथा ऊर्जा के स्वच्छ रूपों को अपनाने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्राथमिकता 7: बुनियादी ढांचा

- सरकार व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और सक्षम नीति और नियामक वातावरण के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बाजार आधारित वित्तपोषण ढांचे की परिकल्पना कर रही है।
- 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण IV शुरू किया जाएगा।

प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास

- सरकार बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष को क्रियान्वित करेगी। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में व्यावसायिक स्तर पर नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ₹1 लाख करोड़ का वित्तपोषण पूल बनाया जाएगा।
- अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।

प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार

- सरकार रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और उच्च आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का दायरा निर्धारित करने के लिए एक व्यापक आर्थिक नीति ढांचा तैयार करेगी। उत्पादन के सभी कारकों की उत्पादकता बढ़ाने और कुशल बाजारों और क्षेत्रों के विकास के लिए सुधार शुरू किए जाएंगे। इसके लिए, राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्धारित किया जाएगा ताकि सुधारों के तेजी से कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा सके और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके।

कर प्रस्ताव

प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा का उद्देश्य इसे अधिक संक्षिप्त और समझने योग्य बनाना है, जिससे विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आए। अपीलों के लंबित मामलों को कम करने के प्रयासों में आयकर विवादों के समाधान के लिए अधिक अधिकारियों की तैनाती और विवाद से विश्वास योजना, 2024 का प्रस्ताव शामिल होगा।
- बजट में पूंजीगत लाभ कराधान को युक्तिसंगत और सरल बनाने के उद्देश्य से कई उपायों का प्रस्ताव किया गया है।
- मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कर न्यायाधिकरणों और न्यायालयों में अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान करने के लिए सुरक्षित बंदरगाह नियमों का विस्तार किया जाएगा, और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
- बजट में दान के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाने और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की संरचना का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त, टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध से मुक्त किया जाएगा।
- निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के प्रस्तावों में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करना, घरेलू क्रूज संचालित करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाना तथा भारत में कच्चे हीरे बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सुरक्षित बंदरगाह दरें प्रदान करना शामिल है।

- विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत की जाएगी।
- कर आधार को बढ़ाने के उपायों में वायदा और विकल्प पर सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाना और शेयर पुनर्खरीद से होने वाली आय पर कर लगाना शामिल है।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए नियोक्ता व्यय की कटौती बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार किया जाएगा।
- नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं के लिए व्यक्तिगत आयकर दरों में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं:

प्रस्तावित		मौजूदा	
आय	**कर की दर**	**आय**	**कर की दर**
₹0-3 लाख	शून्य	₹ 0-3 लाख	शून्य
₹ 3-7 लाख	5 प्रतिशत	₹ 3-6 लाख	5 प्रतिशत
₹ 7-10 लाख	10 प्रतिशत	₹ 6-9 लाख	10 प्रतिशत
₹ 10-12 लाख	15 प्रतिशत	₹ 9-12 लाख	15 प्रतिशत
₹12-15 लाख	20 प्रतिशत	₹ 12-15 लाख	20 प्रतिशत
₹ 15 लाख से अधिक	30 प्रतिशत	₹ 15 लाख से अधिक	30 प्रतिशत

- नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव

- प्रमुख क्षेत्र-विशिष्ट सीमा शुल्क समायोजन में कुछ कैंसर दवाओं और महत्वपूर्ण खनिजों पर पूर्ण छूट, मोबाइल फोन और संबंधित भागों पर शुल्क में कमी, और सौर सेल और पैनल निर्माण में उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त पूंजीगत सामानों के लिए छूट शामिल है। प्रस्तावों में समुद्री भोजन, चमड़ा और कपड़ा निर्यात के लिए इनपुट पर शुल्क कम करना भी शामिल है। स्टील और तांबे के लिए उत्पादन लागत को कम करने, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का समर्थन करने और रसायनों और प्लास्टिक पर शुल्क समायोजित करने के उपायों की भी घोषणा की गई।
- देश में सोने और बहुमूल्य धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।